http://amritkalashtimes.com

अमृत कलश टाइम्स

वर्ष : 18
अंक : 34

प्रयागराज शनिवार 19 अक्टूबर 2024

पृष्ठः– 4, मूल्यः– एक रुपया

पीएम अगले हफ्ते करेंगे रूस का दौरा

● पुतिन ने दिया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता

नई दिल्ली,(एजेंसी)। रूस के कजान में आयोजित इस सम्मेलन में पीएम मोदी के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। लगभग एक साल बाद पहली बार ऐसा होगा कि पीएम मोदी और जिनपिंग एक साथ एक मंच पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22–23 अक्तूबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस का दौरा करेंगे। बता दें कि इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान में किया जा रहा है। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ब्रिक्स सदस्यीय देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। पीएम मोदी इससे पहले जुलाई में भी रूस का दौरा कर चुके हैं। आठ जुलाई को पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया था। वह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन को आयोजित करने के लिए रूस पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन के साथ वार्ता की, जिसके दौरान व्यापार और रक्षा सौदों सहित द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच रूस–यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। बता दें कि फरवरी 2022 में मास्को की तरफ से यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली रूस यात्रा थी। इसके एक महीने बाद ही उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया था। पोलैंड की यात्रा खत्म कर वे ट्रेन से 10 घंटे का सफर करके यूक्रेन पहुंचे थे। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। क्या है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अमेरिका शामिल हैं। हाल ही में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सउदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के सदस्य बने हैं।

यूपी में असीमित क्षमताः सीएम

सीएम योगी बोले, पूरा होगा वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना

● मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तेज वृद्धि दर उत्साहित करने वाली है

● जल्द ही जाई जाएगी आईटी से जुड़ी पॉलिसी

लखनऊ,(एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोजित बैठक में एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्थाश के लिए जारी प्रयासों और परिणामों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में जारी प्रयासों, अब तक के परिणामों और भावी नीति पर विमर्श किया। बैठक में विभिन्न मंत्रीगणों, शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, सलाहकारों, विशेषज्ञों की उपस्थिति रही। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी 10 सेक्टरों में जारी कार्यों की समीक्षा की। कंसल्टिंग एजेंसी डेलॉयट इंडिया ने विस्तार से प्रदेश के आर्थिक परिवेश की वर्तमान स्थिति और संभावित भावी परिणाम, उद्योग जगत की अपेक्षाओं आदि के संबंध में सेक्टरवार विस्तार से जानकारी दी। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विगत 07 वर्षों के नियोजित प्रयासों से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। 2021–22 में प्रदेश की कुल जीडीपी ₹16.45 लाख करोड़ थी जो आज 2023–24 में ₹25.48 लाख करोड़ से अधिक हो गई है। इस वर्ष हमारा जीएसडीपी लक्ष्य ₹32 लाख करोड़ का है। सभी के सहयोग से यह लक्ष्य भी पूरा होगा। इन 07 वर्षों में जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हुई है। उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। सेक्टरवार विकास के हमारे प्रयासों के आशातीत परिणाम मिल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अलग–अलग सेक्टरों के लिए सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का जो लक्ष्य रखा गया, उसके सापेक्ष अधिक वृद्धि देखी गई है। कृषि और सहायक सेक्टर के लिए अनुमानित जीवीए 5.85 लाख करोड़ के सापेक्ष 5.98 लाख करोड़, विनिर्माण के 2.48 लाख करोड़ के सापेक्ष 2.79 लाख करोड़, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन के अनुमानित जीवीए के सापेक्ष 129: की वृद्धि दर्ज की गई है। स्पष्ट है व्यापार, होटल, परिवहन और प्रसारण से संबंधित संचार सेवाओं की वृद्धि दर में तेजी आई है। ऐसे ही हाल अन्य सेक्टरों में भी है। ओवरऑल 2023–24 में राज्य के लिए अनुमानित जीएसवीए 23 लाख करोड़ के सापेक्ष सकल मूल्य वर्धन 23.24 लाख करोड़ रहा है।

जम्मू–कश्मीर मंत्रिमंडल ने अपने पहले प्रस्ताव में राज्य का दर्जा बहाल करने का किया आग्रह

श्रीनगर,(एजेंसी)। जम्मू–कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के पहले प्रस्ताव में राज्य का दर्जा बहाल करने का आह्वान किया गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को

पहली बैठक के दौरान जम्मू–कश्मीर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें केंद्र सरकार से जम्मू–कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया। जानकारी मिली है कि कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री को प्रस्ताव का मसौदा सौपेंगे और उनसे चार अगस्त, 2019 से पहले की तरह राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह करेंगे। कैबिनेट की ओर से पारित प्रस्ताव पर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जम्मू–कश्मीर सरकार ने कल की कैबिनेट बैठक में किसी भी फैसले के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी खुलासा नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट ने ईशा योग केंद्र को दी बड़ी राहत

● सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कार्यवाही बंद की

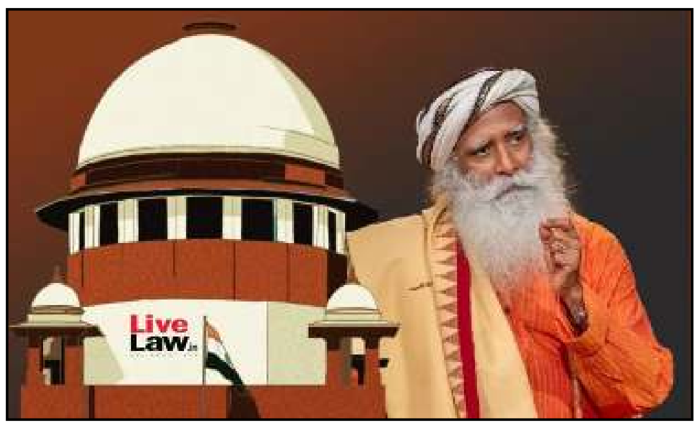

नयी दिल्ली,(एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने योग गुरु जग्गी वासुदेव के कोयंबटूर स्थित ईशा फाउंडेशन के खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय की कार्यवाही का दायरा बढ़ाने को शुक्रवार को अनुचित करार दिया और कार्यवाही बंद कर दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पार्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश पारित किया। पीठ ने महसूस किया कि उच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही के दायरे को बढ़ाना अनुचित था, क्योंकि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अच्छी तरह से परिभाषित है। इस मामले में उच्च न्यायालय की ओर से कार्यवाही का विस्तार करना अनावश्यक था। शीर्ष अदालत ने पाया कि 39 और 42 वर्ष की दो महिलाओं ने इस अदालत के साथ–साथ पुलिस के समक्ष अपने बयान दिए थे कि वे स्वेच्छा से और अपनी स्वतंत्र इच्छा से आश्रम में रह रही थीं। सुनवाई करते हुए पीठ ने फाउंडेशन से यह भी कहा कि वह धर्मनिरपेक्ष कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करे। पीठ ने फाउंडेशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और वी गिरी से कहा, ष्इसका उद्देश्य संगठन को बदनाम करना नहीं है, बल्कि आपको धर्मनिरपेक्ष प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उल्लंघनों को सुधारना होगा।ष शीर्ष अदालत ने ईशा फाउंडेशन के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही के बाद तीन अक्टूबर को उस मामले को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। इसके बाद शीर्ष अदालत की पीठ ने दोनों महिला साध्वियों से वर्चुअली और चौंबर में बातचीत की और पाया कि वे अपनी मर्जी से और बिना किसी दबाव के वहां रह रही हैं। उच्च न्यायालय के निर्देश पर तमिलनाडु पुलिस ने एक अक्टूबर को ईशा फाउंडेशन के आश्रम में तलाशी ली थी।कोर्ट ने की ये टिप्पणी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों महिलाओं के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई बंद करने का आदेश दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले का ईशा योग केंद्र के खिलाफ चल रहे अन्य मामलों पर कोई असर नहीं होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में ईशा योग केंद्र को सलाह देते हुए कहा कि जब आपके आश्रम में महिलाएं और नाबालिग बच्चे हैं तो आपको आंतरिक शिकायत कमेटी गठित करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इस सलाह का उद्देश्य किसी संगठन को बदनाम करना नहीं है बल्कि सिर्फ ये बताना है कि कुछ चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या है मामला रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने ईशा योग केंद्र के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में एस कामराज ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटियों को आश्रम में बंधक बनाकर रखा गया है।

जम्मू–कश्मीर में नए मंत्रियों में हुआ विभागों का बंटवारा

श्रीनगर,(एजेंसी)। जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश में सरकार गठन के बाद नये मंत्रियों को विभाग सौंप दिये हैं। उप मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी को लोक निर्माण (आर एंड बी), उद्योग एवं वाणिज्य, खनन, श्रम एवं रोजगार और कौशल विकास विभाग सौंपे गए हैं। सुश्री सकीना इटू स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण का प्रबंधन करेंगी। इसी तरह जावेद अहमद राणा को

जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और जनजातीय मामलों का प्रभार दिया गया है। जावीद अहमद डार को कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता और चुनाव की जिम्मेदार दी गयी है। सतीश शर्मा खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा सेवा और खेल तथा एआरआई और प्रशिक्षण विभाग संभालेंगे। उपराज्यपाल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर सरकार के कामकाज के लेन–देन नियम, 2019 के नियम 4 (2) के अनुसार मंत्रियों को प्रभार सौंपा। आदेश में यह भी कहा गया है कि इन मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए कोई भी अन्य विभाग या विषय मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। गौरतलब है कि श्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के लिए पांच मंत्रियों को चुना– दो कश्मीर से और तीन जम्मू से।

एनडीए में सीटों के बंटवारे पर मुहर

●68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा, आजसू–जदयू और लोजपा को इतनी सीटें

झारखण्ड,(एजेंसी)। झारखंड भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा–जदयू–आजसू और लोजपा (आर) साथ मिलकर झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है और जल्द ही उम्मीदवारों का भी एलान कर दिया जाएगा। झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। सीट बंटवारे के तहत भाजपा झारखंड की 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आजसू को 10, जदयू को दो और एक सीट लोजपा(आर) को दी गई है। झारखंड भाजपा के सह–प्रभारी और असम सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने यह जानकारी दी। झारखंड भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा–जदयू–आजसू और लोजपा (आर) साथ मिलकर झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है और जल्द ही उम्मीदवारों का भी एलान कर दिया जाएगा। आजसू प्रमुख बोले– जनता हमें साथ देखना चाहती है शुक्रवार को बाबूलाल मरांडी के साथ रांची के भाजपा कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि हम दोनों पार्टियों का बहुत पुराना संबंध है। झारखंड की जनता हमलोगों को साथ देखना चाहती है। राज्य के विकास के लिए और जनता के हित में हमने गठबंधन करने का फैसला किया है। सुदेश महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार के कुशासन से झारखंड का हर वर्ग प्रभावित है। हम यहां दलीय समीकरण के रूप में जरूर यहां बैठे हैं। दूसरी ओर गांव–देहात में धरातल पर जनता का समीकरण भी तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के मुखिया ने जो कारनामे किए हैं, उसकी चर्चा देश–दुनिया में हो रही है। इन सीटों पर चुनाव लड़ेगी आजसू मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, झारखंड विधानसभा की जिन 10 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ेगी, उनमें सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, इचागढ़, मांडू, जुगसलिया, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा, मनोहरपुर शामिल हैं। वहीं जदयू जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ सीट पर चुनाव लड़ेगी। चतरा विधानसभा सीट चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा रामविलास को दी गई है। दो चरणों में झारखंड में होगा मतदान उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 23 नवंबर को नतीजों का एलान किया जाएगा। पहले चरण में राज्य की 43 विधानसभा सीटों पर और दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड में एनडीए का मुकाबला झामुमो के नेतृत्व वाली प्छक्प्। गठबंधन से होगा, जिसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद शामिल हैं।

कंटेंट क्रिएशन का बाजार 2035 तक होगा 480 अरब डॉलर काः सिंधिया

नयी दिल्ली,(एजेंसी)। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कंटेंट क्रिएशन में भारत के नेतृत्व को रेखांकित करते हुए आज कहा कि भारत दुनिया की कंटेंट क्रिएशन राजधानी बनने की ओर अग्रसर है, जिसका बाजार आज के 30 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 480 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। श्री सिंधिया ने यहां चल रही इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में ष्भारत में कंटेंट क्रिएशन में क्रांति लानारू अगले एक अरब उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करनाष शीर्षक पर पैनल चर्चा के दौरान यह बात कही। इस व्यावहारिक सत्र ने

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और कंटेंट क्रिएशन के बीच बढ़ते अंतर्संबंध पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने सूचना तक पहुंच के लोकतंत्रीकरण और डिजिटल क्रांति का नेतृत्व करने के लिए 6जी जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों को अपनाने के लिए भारत की तत्परता पर जोर दिया। श्री सिंधिया ने कंटेंट क्रिएशन में क्रांति लाने में एआई की भूमिका को रेखांकित किया। पैनल ने इस बात पर जोर दिया कि सामग्री निर्माण में एआई राजस्व धाराओं का विस्तार करने, लागत कम करने और नए बाजारों में प्रवेश करने का अवसर है, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में जहां सामग्री उपभोग पैटर्न विकसित हो रहे हैं। चूंकि एआई वास्तविक समय के वैयक्तिकरण और दर्शकों के साथ बातचीत की सुविधा देता है, इसलिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने वाली है। एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, उद्योग, सरकार, शिक्षाविदों, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी और दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य प्रमुख हितधारकों के लिए अभिनव समाधान, सेवाओं और अत्याधुनिक उपयोग के मामलों को प्रदर्शित करने के लिए दुनिया भर में एक प्रसिद्ध मंच बन गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में 400 से अधिक प्रदर्शक, लगभग 900 स्टार्टअप और 120 से अधिक देशों से भागीदारी हो रही है।

सभी के लिए अवसर पैदा करने की भी चुनौती हैः सीतारमण

मैक्सिको सिटी,(एजेंसी)। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए, चुनौतियाँ केवल विकास के आसपास ही नहीं हैं, बल्कि अंतर को पाटना और सभी के लिए अवसर पैदा करना भी है, और इसके लिए जिम्मेदार पूंजीवाद की जरूरत है। श्रीमती सीतारमण ने आज ग्वाडलजारा के चौंबर ऑफ कॉमर्स में टेक लीडर्स राउंडटेबल की अध्यक्षता की, जिसमें श्भारत और मैक्सिको के बीच तकनीकी सहयोग को मजबूत करनाश पर चर्चा की गई। उन्होंने समान स्थिति वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए अवसर और जिम्मेदारियों के बारे में बात की और बताया कि कैसे भारत मैक्सिको एक दूसरे के साथ लाभ उठा सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मैक्सिको निकटवर्ती क्षेत्र के माध्यम से फल–फूल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच सहयोग हुआ है और प्रतिभाओं के आदान–प्रदान के साथ–साथ जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त प्रयास संभव हुए हैं। वित्त मंत्री ने 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम करते हुए भारत में

हो रहे तेजी से बदलाव पर प्रकाश डाला। भारत मैक्सिको के बीच विकास और सहयोग के नए क्षेत्रों का हवाला देते हुए श्रीमती सीतारमण ने उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के संबंध में की गई प्रमुख बजट घोषणा का उल्लेख किया और स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा, कृषि और टिकाऊ शहरों में ए आई के क्षेत्रों में काम करने के लिए भारत में हाल ही में पहचाने गए और घोषित उत्कृष्टता केंद्र के बारे में जानकारी साझा की। वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कि ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जो मैक्सिको के लिए भी प्रासंगिक हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत मैक्सिको भी स्टार्टअप के साथ–साथ शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से इन क्षेत्रों में एक साथ काम करने का पता लगा सकता है।

इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन मैक्सिकन एसोसिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और टीसीएस द्वारा मैक्सिको में भारतीय दूतावास और आर्थिक मामलों के विभाग के सहयोग से किया गया था।

अमृत कलश टाइम्स
हिन्दी दैनिक

चक्रव्यूह

भारत की संसदीय राजनीति की यह सबसे दुखद परिघटना है कि लोक सभा में बजट पर हो रही चर्चा जाति के चक्रव्यूह में फंस गई। विपक्ष के नेतागण शायद इस तथ्य से अनजान हैं कि भारतीय समाज में जाति संघर्ष बढ़ा तो देश की क्षेत्रीय अखंडता पर इसके नकारात्मक परिणाम पड़ सकते हैं।संविधान निर्माता और चिंतक डॉ. अंबेडकर भारतीय समाज की इस बुराई को समझ गए थे। इसीलिए उन्होंने जातिविहीन समाज के निर्माण की कल्पना की थी। आगे चलकर समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने भी जाति तोड़ो को लेकर लंबा अभियान चलाया था। लेकिन विडम्बना है कि बिहार के नेताओं के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को महाभारत में अजरुन को जिस तरह सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह जातिगत जनगणना दिखाई दे रही है।भारतीय राजनीति और समाज का दुखद पहलू है कि आज हर जाति में वर्चस्ववादी नेता पैदा हो गए हैं। ऐसा नेता जाति स्वाभिमान हो गया है। इस तरह से कट्टर जातिवादी नेताओं का समाज और राजनीति में प्रभाव बढ़ता है तो पहले से ही जाति और धर्म में विभाजित समाज आगे चलकर और कितना विभाजित होगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। ठीक है कि जाति गणना सत्ता पाने की सीढ़ी बन सकती है लेकिन इससे सामाजिक विद्वेष बढ़ेगा और अंततरू प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाएगी।

डॉ. लोहिया का विास है कि श्इतिहास साक्षी है कि जिस काल में जाति के बंधन ढीले थे, उसने लगभग उसी काल में घुटने नहीं टेके।य उनका मानना है कि यह गलत धारणा है कि अंदरूनी झगड़ों और छल–कपट के कारण न तो विदेशी हमले हुए और न भारत गुलाम हुआ। इसका सबसे बड़ा और एकमात्र कारण है जाति।1960 और 71 के दशक में डॉ. लोहिया के प्रयासों से समाज में जाति के बंधन कुछ ढीले पड़ने लगे थे। बाद में आरएसएस ने भी हिन्दू समाज की जातियों की एकता को मजबूत करने के लिए अभियान चलाया और आज भी संघ का यह प्रयास जारी है लेकिन लगता है कि जातिगत पहचान और स्वाभिमान का उभार तेजी से हो रहा है।राहुल गांधी इस उभार को और अधिक हवा देने लगे हैं। हालांकि राहुल के जातिगत जनगणना के बयान पर भाजपा नेता के इस जवाब का समर्थन नहीं किया जा सकता जिनकी अपनी जाति का पता नहीं है, वे जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। सदन हो या सड़क जाति पूछना अमर्यादित आचरण के दायरे में ही आता है।

आज का राशिफल

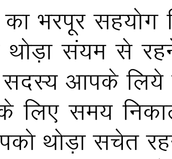

डॉ बिपिन पाण्डेय
ज्योतिष विभाग
लखनऊ विवि

मेष–आज मन खुश रहेगा व जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के आसार हैं आपको थोड़ा संयम से रहने की आवश्यकता होगी। आपके परिवार का कोई सदस्य आपके लिये मार्गदर्शक बनेगा। थकान महसूस होगी। आराम के लिए समय निकालें।

वृष –आज आपको स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य हासिल करने में थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है लेकिन उन्हें इस कड़ी मेहनत का अपेक्षित परिणाम भी हासिल होगा। दिन की शुरुआत में आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है।

मिथुन –आज अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि इससे आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है। पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे। आपको पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है। घर में मरम्मत का काम या सामाजिक मेल–मिलाप आपको व्यस्त रखेगा। व्यापारियों के लिए अच्छा दिन है।

कर्क –दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाए बिना उलझना ठीक नहीं है। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें। धर्म–कर्म में आस्था बढ़ेगी। विरोधी परास्त होंगे। महत्वपूर्ण कार्य में विलंब संभव है। लाभ होगा। अपने प्रेमी या जीवनसाथी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

सिंह –आज पुरानी गलतियों को लेकर भय बना रहेगा। साझेदारी में चल रहा गतिरोध दूर होने के आसार है। आयात–निर्यात के कारोबार में बड़ा लाभ संभव है। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ काम करना आसान रहेगा। दूसरों की गलती अपने पर आ सकती है। काम में देरी से लाभ की मात्रा सीमित होगी।

कन्या –आज के दिन आपको सुख–समृद्धि, कार्यक्षेत्र में उन्नति, सुखद सफल यात्राएं, परिवार और जीवन साथी का सहयोग सब मिलने के आसार हैं। विवाहित व्यक्ति अपने जीवनसाथी में पूर्णतया विश्वास जतायें अन्यथा संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। आपके कर्मक्षेत्र, आपके सम्मान व आपके नाम पर पडने के आसार हैं।

तुलाःआज भाग्य आपके साथ है। लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को नया रूप देने के लिए अच्छा मौका है। आज स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। अचानक सेहत बिगड़ सकती है और कई जरूरी काम भी रुक सकते हैं। परिवार के लोग आपसे थोड़े नाराज हो सकते हैं।

वृश्चिकः आज आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं, इससे बचने के लिए कहीं बाहर जाएं और दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएं।आज जिस नए समारोह में आप शिरकत करेंगे, वहाँ से नयी दोस्ती की शुरुआत होगी। आज आपका प्रिय आपके साथ में समय बिताने और तोहफे की उम्मीद कर सकता है।

धनुः आज आपके परिश्रम से किए गए कार्य में सिद्धि होगी। नौकरी में आप का सम्मान बढेगा। यात्रा के दौरान आप नयी जगहों को जानेंगे। और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। आप अपने प्रिय द्वारा कही गयी बातों के प्रति काफी संवेदनशील होंगे। अगर आप सूझ–बूझ से काम लें, तो आज अतिरिक्त धन कमा सकते हैं।

मकरः आज आपके आय के नए स्रोत बनेंगे। आकस्मिक धन के अवसर मिलेंगे। मित्रों और जीवनसंगिनी के सहयोग से राह आसान होगी। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। दफ्घ्तर का तनाव आपकी सेहत खराब कर सकता है। अपने जज्बात पर काबू रखें। आज आपको अपने प्रिय की याद सताएगी।

कुंभः आज आप करिअर से जुड़े फैसले खुद करें, बाद में इसका लाभ आपको मिलेगा। सहकर्मियों और कनिष्ठों के चलते चिंता और तनाव के क्षणों का सामना करना पड़ सकता है। माता–पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। आज दोस्तों के साथ बाहर घूमना आपके मन को खुशी देगा।

मीनः आज भाग्य पर निर्भर न रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें। आप उन लोगों की तरफ वादे का हाथ बढ़ाएंगे, जो आपसे मदद की गुहार करेंगे। यह दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर होने वाला है। यह दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर होने वाला है।

सरकार की पहली प्राथमिकता जनगणना

अजीत द्विवेदी

नई लोकसभा का पहला सत्र संपन्न हो गया है और अब सरकार मानसून सत्र की तैयारी कर रही है, जिसमें वित्त वर्ष 2024–25 का बजट पेश किया जाएगा। तीन जुलाई को खत्म हुए संसद सत्र में जनगणना को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। सवाल है कि 23 जुलाई को आने वाले बजट में क्या सरकार जनगणना की घोषणा करेगी और उसके लिए जरूरी धन का आवंटन करेगी? कायदे से यह भारत सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि जनगणना कराई जाए। हर 10 साल पर होने वाली जनगणना आखिरी बार 2011 में हुई थी। अभी तक सरकार उसी के आंकड़ों के आधार पर जन कल्याण की योजनाएं बना रही है। सब कुछ अनुमान के आधार पर हो रहा है, जिससे करोड़ों लोगों को सरकार की योजनाओं के दायरे से बाहर छूट जाने की आशंका है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक लोक कल्याण की योजनाओं को पहुंचाने और प्रभावी नीति निर्धारण के लिए जरूरी है कि जनगणना हो।

ध्यान रखने की जरुरत है कि जनगणना होते ही उसके आंकड़े नहीं मिल जाते हैं। अंतिम आंकड़े आने में बहुत समय लगता है। अगर अभी जनगणना होगी और डिजिटल तरीके से होगी, जिसकी संभावना जताई जा रही है तब भी कम से कम दो साल लगेंगे अंतिम आंकड़े आने में। अगर जनगणना डिजिटल नहीं होती तो अंतिम आंकड़े आने में तीन से चार साल का समय लगता। सो, अगर अब भी प्राथमिकता के आधार पर जनगणना होती है तो 2026 से पहले अंतिम आंकड़े नहीं मिल पाएंगे। इससे ज्यादा समय भी लग सकता है। तभी यह आशंका भी जताई जा रही है कि सरकार जनगणना को टाल सकती है। क्योंकि 2024 में अगले तीन चार महीने में चार राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। इस वजह से साल के अंत में ही जनगणना का काम शुरू होगा तो उसके अंतिम आंकड़ 2027 तक आएंगे। इसके दो साल बाद यानी 2029 से 2031 की जनगणना का काम शुरू करना होगा। ऐसे में अभी जनगणना टाली जा सकती है और कुछ अन्य सर्वेक्षणों व पुराने आंकड़ों के आधार पर तब तक काम चलाया जा सकता है।

लेकिन सवाल है कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? नरेंद्र मोदी सरकार ने महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन का जो कानून पास किया है उसमें कहा गया है कि परिसीमन के बाद इसे लागू किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने परिसीमन को लेकर जो संशोधन किया था उसके मुताबिक 2026 तक परिसीमन पर रोक है और उसमें कहा गया है कि उसके बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जाएगा। तभी संभव है कि केंद्र सरकार इसे 2026 के बाद ही कराए या ऐसी टाइमलाइन बना कर कराए कि आंकड़े 2026 के बाद आएं और उसके आधार पर परिसीमन हो और 2029 से महिला आरक्षण भी लागू हो और एक साथ चुनाव का नियम भी लागू हो।

बहरहाल, जनगणना का क्या होगा, यह सरकार जाने लेकिन इसकी

तत्काल जरुरत से इनकार नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 2019 में जनगणना की अधिसचूना जारी कर दी थी और 2020 में पहले चरण में मकानों के सर्वे का काम शुरू होने वाला था। लेकिन उसी समय कोरोना की महामारी फैल गई, जिसकी वजह से पहले चरण का काम भी नहीं हो पाया। हालांकि कोरोना की महामारी खत्म हुए भी दो साल से ज्यादा हो गए हैं। कोराना की दूसरी और बेहद घातक लहर 2021 के जुलाई तक खत्म हो गई थी। उसके बाद 2022 के शुरू तक देश के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी थी। इसके बावजूद जनगणना का काम नहीं शुरू किया गया। तभी सरकार की मंशा पर सवाल भी उठ रहे हैं। अगर सरकार चाहती तो अब तक जनगणना हो चुकी होती और अगले कुछ दिन में प्रारंभिक आंकड़े मिल जाते।

बहरहाल, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरुरत है। क्योंकि नजगणना के आंकड़ों के बगैर प्रभावी नीति निर्धारण संभव नहीं है और न समाज के वंचित व पिछड़े तबके तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा सकना संभव है। यह भी ध्यान रखने की जरुरत है कि जनगणना सिर्फ नागरिकों की संख्या गिनने का जरिया नहीं है। नागरिकों की संख्या का मोटा मोटी अनुमान तो सबको है। सब जान रहे हैं कि भारत की आबादी 142 करोड़ के करीब पहुंच गई है। इस संख्या की पुष्टि भर के लिए जनगणना नहीं होती है। जनगणना एक महती प्रक्रिया है, जिससे ढेरों आंकड़े जुटाए जाते हैं। ये आंकड़े सिर्फ सरकार के काम नहीं आते हैं। प्रशासकों से लेकर नीति निर्धारकों और गैर सरकारी संगठनों से लेकर अर्थशास्त्रियों, वैश्विक संस्थाओं और जनसंख्या के क्षेत्र में काम करने वाले जानकारों को इससे बहुत मदद मिलती है। लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के साथ साथ स्कूल बनवाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अस्पतालों के निर्माण से लेकर बुनियादी ढांचे के निर्माण तक में जनसंख्या के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाले अनाज के वितरण पर इसका बड़ा असर होता है। पीडीएस सिस्टम पर काम करने वाले अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज का मानना है कि 2011 के आंकड़ों के आधार पर अभी तक यह काम हो रहा है और इस वजह से 10 करोड़ के करीब लोग इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे।

जनगणना से नागरिकों की संख्या का आंकड़ा तो मिलता है कि साथ ही देश की विविधता की भी एक तस्वीर सामने आती है। इससे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता की वास्तविक जानकारी मिलती है। इससे अलग अलग मानकों पर और अलग अलग पहलुओं से नागरिकों के अध्ययन की सुविधा प्राप्त होती है। केंद्र सरकार जब राज्यों के लिए अनुदान आदि की योजना तैयार करती है या बजट में इनके प्रावधानों का मौका आता है तो जनगणना के आंकड़े ही उसके निर्धारण का आधार बनते हैं। जनगणना से राज्यों के नागरिकों की वास्तविक आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति का पता चलता है। राज्यों को उनकी आबादी और उसकी वास्तविक आर्थिक स्थितियों के अनुरूप केंद्र सरकार की मदद मिले, इसके लिए जनगणना के आंकड़े जरूरी होते हैं। 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं। वित्त आयोग को केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व के वितरण का संतुलित रास्ता सुझाना होता है। जीएसटी की व्यवस्था लागू होने के बाद यह वितरण थोड़ा विवादित हो गया है। जनसंख्या के आंकड़े इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। संघीय ढांचे के तहत किसी भी राज्य के साथ भेदभाव न हो इसके लिए भी जरूरी है कि जनसंख्या के वास्तविक आंकड़े सामने आएं और राज्यों की आबादी की विविधता और उनकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का पता चले।

साइबर अपराधों में काफी विविधता

सतीश सिंह

भारत में साइबर अपराधों में काफी विविधता आई है। श्तू डाल–डाल, मैं पात–पात्य की तर्ज पर अपराधी अब नये–नये तरीकों से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। नई मोडस ऑपरेंडी है श्डिजिटल हाउसअरेस्ट्य।

इस तकनीक की मदद से ऑनलाइन फ्रॉड में काफी तेजी आई है। उदाहरण के तौर पर,11 मई को एक बुजुर्ग डॉक्टर को डिजिटली हाउसअरेस्ट करके 45 लाख रुपये ठगे गए। 15 अप्रैल को इंदौर के एक दंपति को 53 घंटों तक हाउसअरेस्ट करके रखा गया और लाखों रुपये ठगे गए। 6 जुलाई को वाराणसी में 3 दिनों तक डिजिटल हाउसअरेस्ट के जरिए सोनारपुरा के निहार पुरोहित से 28.75 लाख रुपये ठगे गए।

आजकल ऑनलाइन गेमिंग के जरिए भी ठगी की जा रही है। कूरियर, रिश्तेदार, दोस्त की गिरफ्तारी आदि की धमकी, अश्लील वीडियो आदि नये–नये तरीकों की मदद से ठगी करने की वारदात में तेजी आई है। स्नैप चौट, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी अब ठगी के साधन बन गए हैं। मित्र या रिश्तेदार की फर्जी प्रोफाइल बनाकर ऐसी ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई और पिछले दशक में भारतीय बैंकों में 65017 धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए। ये आंकड़े निश्चित रूप से डराने वाले हैं।

हाल के वर्षो में कॉल फॉरवर्डिग के जरिए साइबर अपराध करने की घटनाओं में उल्लेखनीय तेजी आई है। टेलीकॉम कंपनियां उपभोक्ताओं को कॉल फॉरवर्डिग की सुविधा देती हैं, जिसके तहत कॉल एवं एसएमएस को फॉर्वड किया जाता है। इस सुविधा का इस्तेमाल उपभोक्ता तब करते हैं, जब मीटिंग या किसी जरूरी काम में व्यस्त होते हैं, ताकि कोई जरूरी कॉल मिस न हो। इसके जरिए स्कैमर कॉल करके उपभोक्ताओं को यह कहता है कि हम आपकी टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी से बोल रहे हैं। हमने नोटिस किया है कि आपके नंबर पर नेटवर्क की समस्या है। समस्या को दूर करने के लिए आपको श्स्टार 401 हैशटैगय नंबर डायल करना होगा।

यह नंबर डायल करने के बाद उपभोक्ता को अंजान नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही, उपभोक्ता कॉल करता है, उसके सभी कॉल और मैसेज स्कैमर के पास पहुंच जाते हैं। अनुसंधानकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने हाल ही में श्विश्व साइबर अपराध सूचकांक्य तैयार किया है, जिसके अनुसार साइबर अपराध के मामले में भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है। इस सूचकांक में 100 देशों को शामिल किया गया है। इसके मुताबिक साइबर अपराध के मामले में रूस शीर्ष पर है, जबकि यूक्रेन दूसरे, चीन तीसरे, अमेरिका चौथे, नाइजीरिया पांचवें, रोमानिया छठे और उत्तर कोरिया सातवें स्थान पर है। बीते कुछ वर्षो से गूगल सर्च इंजन पर लोग अपने हर प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं। ऐसे मनोविज्ञान को दृष्टिगत कर ठग नामचीन भुगतान एप्स जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के नाम से अपना नंबर इंटरनेट पर सहेज रहे हैं जिसके कारण खुद से लोग हैकर्स के जाल में फंस जाते हैं।

अब तो ब्राउजरएक्सटेंशनके डाउनलोडिंग के जरिए भी साइबर अपराध किए जा रहे हैं। यह काम वायरस के जरिए किया जाता है। सार्वजनिक चार्जर पोर्ट के माध्यम से भी मोबाइल एवं लैपटॉप संक्रमित हो जाते हैं। क्रोम, मोजिला आदि ब्राउजर के जरिए किए गए ऑनलाइन लेन–देन ब्राउजर के सर्वर में सेव हो जाते हैं, जिन्हें सेटिंग में जाकर डिलीट करने की जरूरत होती है, लेकिन अज्ञानतावश लोग ऐसा नहीं करते हैं, और इसका फायदा साइबर ठगों को मिल जाता है।

फिशिंग के तहत किसी बड़ी या नामचीन कंपनी या फिर यूजर की कंपनी का फर्जी बेवसाइट बनाकर, जिसका स्वरूप असली बेवसाइट जैसा होता है से लुभावने मेल किए जाते हैं, जिसमें मुफ्त में महंगी चीजें देने की बात कही गई होती है। मोबाइल का चलन बढ़ने के बाद हैकर्स एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए भी ऑफर वाले मैसेज भेजते हैं, जिनमें मैलवेयर युक्त हाइपर लिंक दिया हुआ होता है।मैलवेयर, कंप्यूटर या मोबाइल या टैब में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के साथ–साथ यूजर की वित्तीय जानकारी जैसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड का विवरण, उनके पार्सवड, ओटीपी, मोबाइल नंबर, पता, बैंक खाता नंबर, जन्मतिथि आदि चुरा लेता है। यह यूजर की जानकारी के बिना उसके ईमेल खाते से दूसरे को फर्जी ईमेल भी भेज सकता है और इसके जरिए ठगी करने के साथ–साथ संवेदनशील जानकारी अवांछित लोगों को बेची भी जा सकतीं है। साथ ही साथ, इसकी मदद से किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी धूमिल किया जा सकता है।

आजकल साइबर अपराधी फोन कॉल्स या एसएमएस द्वारा लोगों को बिना कर्ज लिए ही कर्जदार बता कर उनसे पैसों की वसूली कर रहे हैं। ऐसी ब्लैकमेलिंग छोटी राशि मसलन 2000 से 5000 रु पये के लिए ज्यादा की जा रही है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोग पुलिस में शिकायत नहीं करें। लोन रिकवरी एजेंट यह धमकी देते हैं, आपने हमसे कर्ज लिया है और अगर दो–तीन दिनों में पैसे वापिस नहीं करेंगे तो आपकी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी या आपके सगे–संबंधियों या सहकर्मियों के साथ साझा कर दी जाएंगी और सबूत के तौर पर वे मोर्फ्ड तस्वीरें और वीडियो भेजते हैं। मोबाइल एप से लोन लेना सूदखोर या महाजन या साहूकार से भी ज्यादा खतरनाक है।कई बार लोन रिकवरी एजेंट लोगों से सिर्फ पैसे ही नहीं ठगते हैं, बल्कि समाज में उन्हें बदनाम भी कर देते हैं। अगर लोग ब्राउजिंग सेशन के दौरान संदेहास्पद पॉपअप से सतर्क रहें, और सुनिश्चित करें कि वेबसाइट्स या मोबाइल या पब्लिक लैपटॉप या डेस्कटॉप पर कार्ड की जानकारी साझा नहीं करेंगे, अंजान नंबर या ईमेल आईडी से आए अटैचमेंट को तुरंत डिलीट कर देंगे और ऑनलाइन लॉटरी, कैसिनो, गेमिंग, शॉपिंग या फ्री डाउनलोड वाले मैसेज की उपेक्षा करेंगे तो फिशिंग मेल या एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए फॉर्वड होने वाले संदेहास्पद हाइपर लिंक के जाल से बचा जा सकता है। मामले में सावधानी ही बचाव है। लालच नहीं करें। यह सभी समस्याओं की जड़ है। मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं आएं। धमकी मिलने पर पुलिस की मदद लेने से हिचकें नहीं। तभी साइबर अपराध का शिकार बनने से बचा जा सकता है।

सूडानवासी की किसी को फिक्र नहीं

श्रुति व्यास

सूडानवासी दुनिया के सबसे बड़े विस्थापन संकट की पीड़ा झेल रहे हैं। लेकिन किसी को उनकी फिक्र नहीं है। और हो भी क्यों? क्या सूडान हमेशा से उथल–पुथल और उत्पातों के लिए जाना नहीं जाता रहा है? क्या अकारण टकरावों में उलझे रहना ही इस अफ्रीकी देश की किस्मत नहीं है?

सूडान पश्चिमी ताकतों की प्राथमिकता की सूची में हमेशा से बहुत नीचे रहा है। शक्तिशाली पश्चिमी नेताओं की इस देश में न के बराबर रूचि है। वे या तो प्रतिबंध लगाकर उसे दुनिया से अलग–थलग कर देते हैं, या फिर, जैसा कि उन्होंने क्रांति के बाद किया, जल्दबाजी में और बिना सोचे–विचारे आपस में लड़ रहे दो सशस्त्र पक्षों को समझौते के लिए बाध्य करते हैं। नतीजा यह कि सूडान फिर एक ऐसा देश बन जाता है, जिसमें सशस्त्र संघर्ष जारी रहते हैं और सत्ता चंद हाथों में केंद्रित रहती है।

मगर सूडान की ओर ध्यान देना जरूरी है।

सूडान अफ्रीका के सबसे बड़े देशों में से एक है। उसके पास लाल सागर का मनोरम तटीय इलाका है, नील नदी के किनारे उपजाऊ जमीन है और ऐसी सांस्कृतिक और नस्लीय विविधता है जो उसे अरब और अफ्रीकी संस्कृतियों का मिलनस्थल बना सकती है। सूडान पर हमेशा से गिने–चुने लोगों का राज रहा है जो न तो सत्ता और न ही संसाधन किसी दूसरे से साझा करने में विश्वास रखते हैं। आज सत्ता को लेकर चल रही खींचातानी का नतीजा वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहां के लोगों को कयामत जैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है।

सन् 2023 में शुरू हुए युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, दसियों लाख अपने घर छोडने को बाध्य हुए हैं, और शहर के शहर बरबाद हो गए हैं। हत्याएं, यंत्रणा, दुष्कर्म, अकाल, बीमारियांदृ इस देश के लोगों ने क्या नहीं झेला है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन हालातों को ष्हाल के इतिहास की सबसे सबसे भयावह मानवीय आपदाष बताया है, जिससे लगभग ढाई करोड़ लोग पीड़ित हैं।सन् 1965 में स्वतंत्र होने के बाद से ही सूडान में गृहयुद्ध एवं तख्तापलट का लम्बा सिलसिला चल रहा है। पिछले वर्ष वहां की सेना (एसएएफ) और एक अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ) के बीच सशस्त्र टकराव शुरू होने से एक और गृहयुद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों के बीच संबंध कभी अच्छे नहीं थे। मगर तानाशाह राष्ट्रपति उमर अल–बशीर का दोनों पर नियंत्रण था और इसलिए वे खुलकर एक दूसरे से नहीं भिड़े। फिर एक जन आंदोलन के कारण अल–बशीर का तख्तापलट हो गया। कुछ समय तक सेना और आरएसएफ ने एक–दूसरे के साथ सत्ता साझा की मगर फिर दोनों ने तय किया कि एकछत्र राज के बिना उनका काम नहीं चलने वाला है।

राजधानी खार्तूम पर आरएसएफ का कब्जा हो गया है, जो देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। देश के अन्य हिस्सों पर भी उसका नियंत्रण कायम होता जा रहा है। नागरिकों को लूटा जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं और उनकी हत्याएं की जा रही हैं। आरएसएफ पर यह आरोप भी है कि उसने दारफुर में अश्वेत अफ्रीकियों का पूरी तरह सफाया करने का प्रयास किया। नस्लीय सफाई का यह आरोप विश्वसनीय है।

आरएसएफ का गठन सेना ने ही कुख्यात जंजावीड सैनिकों के बचे–खुचे दस्तों से किया था। सेना ने जंजावीड सैनिकों की मदद से दारफुर क्षेत्र में वहशी तरीके से विद्रोह को कुचला था। मगर अब सेना द्वारा गठित आरएसएफ, उसी के लिए भस्मासुर बन गया है।

दोनों पक्षों पर नागरिकों से लूटपाट और दुष्कर्म करने और लोगों की जान लेने और मानवीय सहायता पहुंचाने में बाधा डालने के आरोप हैं। कुछ इलाके पूरी तरह से शेष देश से कट गए हैं और वहां मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी चीजें पहुंचाना भी संभव नहीं रह गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रहने वाले जिंदा रहने के लिए पत्तियां और बीज खाने को बाध्य हैं।

हिंसा के चलते दसियों लाख सूडानियों को अपने घर छोडने पड़े हैं। दुनिया के हर आठ में से एक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (ऐसे लोग, जिन्हें अपने घरों से पलायन करना पड़ा लेकिन जिन्होंने अपना देश नहीं छोड़ा है) सूडान में हैं, जिससे यह अपनी तरह का विश्व का सबसे भीषण संकट बन गया है। अब लोग सूडान की सीमा पार कर दूसरे देशों में भी जा रहे हैं।पड़ोसी चाड की सरकार के अनुसार इस वर्ष के अंत तक लगभग दस लाख शरणार्थी सूडान से चाड पहुंच सकते हैं। देश की सीमा पर पहुंचने वालों की बढ़ती संख्या के लिए खाने की व्यवस्था करना चाड के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया है और वहां हाल में देशव्यापी श्खाद्य एवं पोषणहार आपातकालय लगा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रपट में भविष्यवाणी की गई है कि सूडान में आर्थिक संकुचन पिछले दशक में सीरिया एवं यमन में हुए संकुचन से दो गुना अधिक होगा।

युद्ध की शुरुआत के समय सूडान अंतरराष्ट्रीय खबरों की सुर्खियों में रहा। यह पश्चिम एवं अन्य देशों की गहन चिंता का विषय था। लेकिन आज एक साल बाद सूडान का संकट केवल उसका अपना संकट बनकर रह गया है। कोई उसके बारे में बात नहीं करता, किसी को उसकी परवाह नहीं है। सारी दुनिया की नजरें दो अन्य बड़े युद्धों पर केंद्रित है और सूडान को भुला दिया गया है। पश्चिमी मध्यस्थों का ध्यान उन दोनों युद्धों पर केंद्रित है, और अफ्रीका के अन्य देशों के नेता या तो अपने–अपने देशों की आंतरिक समस्याओं में उलझे हैं या वे सूडान को लेकर बेफिक्र हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी सूडान से आंखे फेर ली हैं और सूडान में चल रहा युद्ध किसी को नहीं दिख रहा है। वहां के गंभीर मानवीय संकट के बावजूद उस देश को भुला दिया गया है। युद्ध के और बड़े इलाके में फैलने का खतरा भी है। इसके अलावा, संयुक्त अरब अमीरात सूडान के संकट से फायदा उठाने की कोशिश में है। वह आरएसएफ का समर्थन कर रहा है, जिससे युद्ध के और लंबा खिंचने के हालात बन रहे हैं।सूडान पर ध्यान देने की जरूरत है। वहां की समस्याओं को हल करने की जरुरत है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारी पीढ़ी को एक ऐसी पीढ़ी के रूप में याद किया जाएगा जो एक देश की पूरी की पूरी आबादी का सफाया होते चुपचाप देखती रही।

डीएम ने ०२ अधिकारियों को स्पष्टीकरण का दिया निर्देश

सीएम डै□ाबोर्ड पोर्टल के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ समीक्षा की,

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कैम्प कार्यालय सभागार में सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर कार्यो/योजनाओं के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सीएम डैशबोर्ड पर विद्युत विभाग की समीक्षा में

➢ विद्युत विभाग के कार्यो में लापरवाही पर अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को दी गयी प्रतिकूल प्रविश्टि,

➢ आगामी लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु फैमिली आईडी बनवाने के लिये लोगों करें प्रोत्साहित–डीएम

➢ सीएम डै□ाबोर्ड पर योजनाओं की रैकिंग ठीक रखें, अन्यथा होगी कार्रवाई–जिलाधिकारी

आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतें डिफाल्डर श्रेणी में पाये जाने, खराब ट्रान्सफार्मर की शिकायत व लम्बित बिल भुगतान के प्रकरण पर जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत सत्यपाल को कड़ी फटकार लगायी और प्रतिकूल प्रविष्टि देने हेतु निर्देशित किया। सीएम डैशबोर्ड की बैठक में ए0आर0 को–आपरेटिव एवं खनन इन्सपेक्टर अनुपस्थित पाये गये जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया। पशुपालन विभाग की समीक्षा में रैकिंग ठीक नही पायी गयी जिस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुये मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि गौशालाओं की बैठक करायें तथा गौशालाओं हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जाये।

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन अधिक संख्या में लम्बित पाये जाने पर नाराजगी जतायी और निर्देशित किया कि एक सप्ताह के अन्दर वृद्धावस्था पेंशन के लम्बित आवेदनों का निस्तारण करायें। इसी प्रकार सीएम डैशबोर्ड पर लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, माध्यमिक शिक्षा, पर्यटन विभाग, प्रोबेशन विभाग, उद्योग विभाग, सेतु निर्माण, राजस्व विभाग की रैकिंग ठीक न पाये जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर जिन विभागों की योजनाओं में रैकिंग ठीक नही है वह रैकिंग ठीक कर लें अन्यथा की स्थिति में आगामी माह में विभागों की रैकिंग ठीक नही पायी जायेगी तो उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होने अधिकारियों से कहा कि निरन्तर सीएम डैशबोर्ड की निगरानी करते रहे और अपने विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें, निर्धारित समयावधि में निस्तारित करें, सभी सम्बन्धित विभाग सीएम डैशबोर्ड को गम्भीरता से लें, सीएम डैशबोर्ड पर योजनाओं की रैकिंग ठीक रखें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में कदापि न जाने पाये, शिकायतों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण करायें और आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तायुक्त ढंग से किया जाये और सम्बन्धित शिकायतकर्ता से फोन पर वार्ता भी की जाये।

''फैमिली आईडी–एक परिवार–एक पहचान'' की समीक्षा के दौरान आवेदनों की संख्या कम पाये जाने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु जनता को फैमिली आईडी बनवाने हेतु प्रोत्साहित करें और इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय तिवारी, जिला विकास अधिकारी कृष्ण कुमार, परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रियंका सोनी व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

पूर्व डिप्टी सीएम ने किया महाअभियान की समीक्षा

अयोध्या (आरएनएस)। सर्किट हाउस में पूर्व डिप्टी सीएम व राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने महानगर तथा जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता महाअभियान की समीक्षा की गई। उन्होंने पदाधिकारियों से एक–एक कर सदस्यता अभियान की प्रगति की जानकारी ली। सदस्यता अभियान में तेजी लाने तथा

➢ सदस्यता के अगले चरण में विशिष्ट व्यक्तियों को बनाया जाएगा भाजपा का सदस्य

➢ पार्टी द्वारा चलाया जाने वाला सबसे बड़ा अभियान है सदस्यता महाअभियान रू दिनेश शर्मा

घर–घर सम्पर्क व संवाद स्थापित कर लोगों को पार्टी का सदस्यता बनाने का निर्देश दिया। मोर्चा, प्रकोष्ठ तथा विभाग के पदाधिकारियों को अभियान में सक्रियता बढ़ाने के लिए कहा।

पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि सदस्यता महाअभियान पार्टी द्वारा चलाया जाने वाला संवाद तथा सर्मपक का सबसे बड़ा अभियान है। अभियान के दौरान ही युवाओं को पार्टी की नीतियों से जोड़ा जाता है जिससे नए कार्यकर्ताओं बनते है। संवाद तथा सम्पर्क की इस प्रक्रिया में सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा की नीतियों के साथ, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यों के बारे में चर्चा भी करनी है। उन्होंने कहा कि सदस्यता के अगले चरण में विशिष्ट व प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलानी है। जिसके लिए विभिन्न स्थानों पर कैम्प लगा कर सदस्यता कराई जाए। अतिविशिष्ट व्यक्तियों से पदाधिकारी समय लेकर सम्पर्क करें तथा उन्हें पार्टी से जोड़े।

इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम ने लाल कुर्ती वार्ड सं. 2 में सदस्यता कैम्प लगाया। विधानसभा रूदौली में विधायक रामचन्दर यादव के साथ सदस्यता अभियान में भाग लिया। बैठक में महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, सहकारी बैक के सभापति धर्मेन्द्र प्रताप सिंह टिल्लू, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित, अवधेश पाण्डेय बादल, ओम प्रकाश सिंह, अभिषेक मिश्र, सभी मंडलों के अध्यक्ष, शैलेन्द्र कोरी, सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

हाटा व पडरौना नगर पालिका को नगर विकास मंत्री ने किया सम्मानित

कुशीनगर।प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री ने कुशीनगर जनपद के दो नगर निकायों को पीएम स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्य किये जाने पर राष्ट्रीय व राज्य स्तर पुरस्कार से सम्मानित किया है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में उप जिलाधिकारी, परियोजना अधिकारी डूडा मो0 जफर के निर्देशन में डूडा कुशीनगर द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना में कुशीनगर जनपद के हाटा नगर पालिका परिषद द्वारा सर्वाधिक लोन वितरण किये जाने पर राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दो पुरस्कार एवं पडरौना नगर पालिका परिषद को राज्य स्तर के पुरस्कार के लिए डूडा के शहर मिशन प्रबंधक राजदीप यादव, पडरौना नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संतराम सरोज, हाटा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मीनू सिंह व नगर पालिका कर्मी अजय कुमार शर्मा, विवेक श्रीवास्तव को पीएम स्वनिधि योजना में सर्वाधिक लोन वितरण कराने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला।

संक्षेप

स्कार्पियो की ठोकर से किशोर घायल

बस्ती डुमरियागंज मार्ग पर सोनहा थाना क्षेत्र के नरखोरिया पड़ाव पर स्कार्पियो की ठोकर से साइकिल सवार दो किशोर घायल हो गए। सोनहा थाना क्षेत्र के बेइली निवासी 16 वर्षीय सुदीश पुत्र विजय कुमार शुक्रवार को गांव के ही 13 वर्षीय शाहआलम पुत्र मुबारक अली के साथ नरखोरिया के पास मछली पकड़ने जा रहा था। अभी दोनों नरखोरिया पड़ाव पर पहुंचे ही थे कि अचानक बस्ती की ओर से आ रही स्कार्पियो की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से घायल शाह आलम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा (सिद्धार्थनगर) ले जाया गया। जबकि सुदीश का स्थानीय चिकित्सक से इलाज कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कार्पियो को अपने कब्जे में ले लिया है।

छह पर गबन का मुकदमा

बस्तीरू कलवारी थानाक्षेत्र के पकड़ी छब्बर गांव में मनरेगा गाईड लाइन के विपरीत काम करा कर 1.20 लाख रुपये हड़प लेने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अदालत के आदेश पर पूर्व ग्राम प्रधान अर्चना देवी निवासी पकडी छब्बर, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सरोज कुमार चौधरी, रोजगार सेवक व जेई मनरेगा, व बहादुरपुर ब्लाक के तत्कालिन बीडीओ पर मुकदमा दर्ज कर प्रकरण की जांच–पड़ताल शुरू कर दी है।

हड़प लिए छात्रवृत्ति के रुपये

बस्तीरू कलवारी थानाक्षेत्र के बैडारी मुस्तहकम गांव में संचालित सीएससी संचालक ने स्कूली छात्रा के खाते में आए छात्रवृत्ति के 44 हजार रुपये हड़प लिए । पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर सीएससी संचालक दिवाकर पुत्र बदरी निवासी ग्राम छितही, थाना महुली, जिला सन्तकबीरनगर के खिलाफ जालसाजी कर रुपये हड़प लेने का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

स्मृति द्वार का लोकार्पण किया गया

हरदोई(आरएनएस) ।वर्ष 1971 में भारत– पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपना जीवन बलिदान करने वाले ग्राम म्योरा ,बिलग्राम निवासी अमर शहीद वीर सैनिक जैराम धोबी की स्मृति में उनके पुत्र जगतराम द्वारा निर्मित स्मृति द्वार का अध्यक्ष जिला पंचायत प्रेमावती व क्षेत्रीय महामंत्री भाजपा अवध क्षेत्र अनु मोर्चा पीके वर्मा द्वारा लोकार्पण किया गया ।इस अवसर पर अध्यक्ष प्रेमावती ने अमर शहीद को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए कहा कि हमारे देश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए अपना जीवन न्योछावर करने वाले अमर शहीद वीर जैराम को समर्पित इस स्मृति द्वार का लोकार्पण करना मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है। इस स्मृति द्वार के माध्यम से हम उनके संघर्ष और बलिदान को सदा याद रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। क्षेत्रीय महामंत्री पीके वर्मा ने वीर शहीद को नमन करते हुए कहा कि कर्तव्य पथ पर अपने प्राण न्ध्यौछावर करने वाले अमर शहीद वीर जैराम की बहादुरी और बलिदान के अचल प्रतीक के रूप मे स्थापित यह स्मृति द्वार न केवल अमर शहीद की पुण्य स्मृति को सदैव जीवित रखेगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए कर्तव्य पालन का प्रेरणा स्रोत भी बनेगा। लोकार्पण समारोह में प्रमुख रुप से अमर शहीद पुत्र जगतराम एवं शिवपाल वर्मा, दिनेश वर्मा व डाल सिंह फौजी सहित ग्राम व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

एक मु□त समाधान योजना 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक लागू

प्रतापगढ़। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) डा0 आकांक्षा दीक्षित ने बताया है कि प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 लखनऊ के द्वारा निगम के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं में वितरित ऋण के बकायेदारों से वसूली हेतु नवीन एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) दिनांक 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू करते हुये लाभार्थी के ऋण खातों में लगाया गया दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ करते हुये ऋण जमा करने की निर्धारित अवधि (36 माह से लेकर 60 माह जारी स्थिति हो) तक का ही साधारण ब्याज की दर से गणना कर देय धनराशि एक मुश्त जमा कराकर खाता बन्द किये जाने की योजना लागू की गयी है। शासन द्वारा संचालित नवीन एक मुश्त समाधान योजना का लाभ बकायेदार अधिक से अधिक उठायें।

विचार संगोष्ठी का हुआ आयोजन

सुलतानपुर (आरएनएस)। कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान सुल्तानपुर के शिक्षा संकाय (एम.एड.–प्रथम सेमेस्टर) में शनिवार के दिन एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार संगोष्ठी का विषय मूल्य आधारित शिक्षा की अनिवार्यता रहा। यह विचार संगोष्ठी शिक्षा संकाय के विभागाध्यक्ष प्रो बिहारी सिंह के दिशा निर्देशन में एमएड प्रथम सेमेस्टर की प्रशिक्षु चित्रा पांडेय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। चित्रा ने बताया कि आज के समय में छात्रों में मूल्यों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। छात्रों में मूल्यों के विकास के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की। इस अवसर पर प्राध्यापकों में डॉ बनवारी, दिलीप कुमार सिंह, श्रीमती कंचन, डॉ संतोष कुमार सिंह, सन्तोष सिंह कुशवाहा और एम एड के प्रशिक्षुओं में चित्रा, निवेदिता, शिवाकांत, जिक्रा, जितेंद्र आदि मौजूद रहे।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में कुछ वादो का हुआ निस्तारण

सुलतानपुर। कृत्तिका ज्योत्स्ना व पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर सोमेन बर्मा द्वारा तहसील सदर में सुनी गई फरियादियों की समस्याएं एवं जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने–अपने सर्किल के तहसील पर सम्पूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जमीनी विवाद से सम्बंधित सभी प्रकरणों में पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीमों द्वारा गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण हेतु दिए गए निर्देश। जनपद के समस्त थानों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सुलतानपुर व पुलिस अधीक्षक महोदय सोमेन बर्मा के द्वारा तहसील सदर पर राजस्व विभाग के अधि0ध्कर्म0 गणों की उपस्थिति में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर कुछ का मौके पर निस्तारण किया गया तथा कुछ के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण हेतु सम्बंधित को निर्देशित किया गया व जमीनी विवाद सम्बंधित सभी प्रकरणों में पुलिस व राजस्व की टीमों द्वारा संयुक्त रुप से प्रकरण का निस्तारण किया जाए जिससे फरियादियों को अलग–अलग भटकना न पड़े व प्रकरणों का त्वरित व न्याय पूर्ण निस्तारण हो सके तथा जमीन सम्बंधित थाना स्तर, आईजीआरएस या अन्य सभी माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों को सम्पूर्ण समाधान दिवस रजिस्टर में अंकित करने एवं सम्पूर्ण समाधान दिवस पर दोनों पक्षों को बुलवाकर पुलिस व

सतत ग्रामीण आजीविका पर हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी

चित्रकूट। भारत सरकार के नीति आयोग और दीनदयाल शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सतत ग्रामीण आजीविका पर राष्ट्रीय संगोष्ठी मंगलवार को नीति आयोग नई दिल्ली के सभागार में आयोजित की गई।

दीनदयाल शोध संस्थान कोषाध्यक्ष वसंत पंडित के संयोजकत्व में ग्रामीण विकास से संबंधित पिछ्ले तीन वर्ष से एक वैश्विक विमर्श पर काम कर रहा है। यह सेमिनार इसी कड़ी में नीति आयोग के ग्रामीण विकास अनुभाग ने आयोजित की। उदघाटन सत्र में आयोग के कार्यक्रम निदेशक जयंत सिंह ने स्वागत किया। कलिंग इंस्टीटयट के डा. सूरज कुमार ने प्रस्तावना रखी। नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश कुमार ने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उभरते रुझान पर वक्तव्य दिया। मुख्य वक्तव्य प्रख्यात चिंतक शेषाद्रीचारी ने भारतरत्न नानाजी के ग्रामीण विकास के चित्रकूट मॉडल को रखा और संस्थान के प्रयासों को बताया। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव एनएन सिन्हा ने ग्रामीण क्षेत्र में लघु ऋण, उद्यमिता और रोजगारपरकता, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के प्रो अशोक विशनदास एवं नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष भानवाला ने ग्रामीण आय बढ़ाने के लिये बाजार जुड़ाव और मूल्य श्रंखला तथा भारत सरकार के पूर्व ग्रामीण विकास के सचिव अमरजीत सिन्हा ने ग्रामीण आजीविका के लिए बाजार आधारित समाधान पर अपने विचार व्यक्त किये।

दूसरा सत्र में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति डा. एके सिंह, नीति आयोग की कार्यक्रम निदेशक डा. नीलम पटेल, हैदराबाद के डा. सेंथिल विनयागम ने अपने विचार रखे। पद्मश्री उमाशंकर पांडेय, केन्द्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष एबी पांड्या एवं डा. आलोक सिक्का ने सतत ग्रामीण विकास एवं जल सुरक्षा की जानकारी दी। सत्र का संचालन दीनदयाल शोध संस्थान के कोषाध्यक्ष वसंत पंडित ने किया। संस्थान के प्रधान सचिव अतुल जैन ने सार सक्षेप पर प्रकाश डाला।

बीडीसी हत्याकांड में नामजद छह गिरफ्तार

मोतिगरपुरध्सुल्तानपुर)(आरएनएस)। क्षेत्र पंचायत सदस्य अवधेश सिंह हत्याकांड के छह नामजद हत्यारोपियों को पुलिस ने स्थानीय थाना क्षेत्र के अलग–अलग स्थानों से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी जेल भेजे गए। हत्यारोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद हुए हैं।गुरुवार को थाना क्षेत्र के मोतिगरपुर–दोस्तपुर मार्ग पर स्थित गोपालपुर बड़ागांव में देवकला बाबा स्थान पर पहले घात लगाए बैठे बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था। आरोप के मुताबिक बीडीसी अवधेश सिंह दीवानी कोर्ट से भतीजे शानू के साथ घर लौट रहे थे, जब वे गोपालपुर बड़ागांव में स्थित देवकला बाबा धाम व विधायक के महाविद्यालय के पास पहुंचे तो बदमाशों ने लाठी–डंडे व लोहे की रॉड से दोनों पर हमला बोल दिया। अवधेश का फौजी भतीजा मौके से भाग निकला जिससे वह गंभीर चोट से बच गया। लेकिन अवधेश को आरोपियों ने घेरकर बुरी तरह से पीट दिया। उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज लाया गया और जहां से इलाज के लिए ने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। देररात करीब दो बजे अवधेश की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर पैतृक गांव मुड़हा पहुंचते ही कोहराम मच गया। अगले दिन शुक्रवार को परिजनों ने पुलिस के सामने जमकर हंगामा काटा। देरशाम लखनऊ से पोस्टमार्टम के बाद शव घर आया और शनिवार दोपहर में दियरा राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस प्रकरण में मृतक के भाई रणधीर सिंह की तहरीर पर मुड़हा निवासी विपिन सिंह, हिमांशु सिंह उर्फ रिशू सिंह, प्रिंस सिंह, रिषभ सिंह ऊर्फ लक्की सिंह, अमन सिंह और कादीपुर के घूरीपुर निवासी अतुल सिंह उर्फ अर्जुन सिंह के विरुद्ध हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में दर्ज हुआ था। बीडीसी की मौत के बाद हत्या की धारा बढ़ा दी गई है। सीओ जयसिंहपुर प्रशांत सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों को थाना क्षेत्र के अलग–अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया गया। जहां से सभी जेल भेजे गए। उन्होंने बताया कि मृतक के पुत्र निखिल सिंह उर्फ शिवम सिंह को सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर मिली हत्या की धमकी के मामले में अज्ञात के विरुद्ध आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज करके साइबर सेल को जांच दी गई है।

फर्जी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बनकर मेडिकल स्टोरों पर मार रहे थे छापा ,मुकदमा

मल्लावांध्हरदोई(आरएनएस) ।स्वास्थ्य विभाग के फर्जी अधिकारी बनकर मेडिकल स्टोर की जाँच करने वाले महिला समेत चार लोगों के खिलाफ मेडिकल स्टोर के संचालकों ने कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस ने एक व्यक्ति को नामजद करते हुए तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है।

क्षेत्र में संचालित मेडिकल स्टोरों पर फर्जी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बनकर छापेमारी कर अवैध वसूली कर रहे लोगों के विरूद्ध मेडिकल संचालकों ने देर शाम कोतवाली पहुंच कर तहरीर दी है ।क्षेत्र के मेडिकल स्टोर संचालक जसवंत , अवधेश कुमार ,राकेश,अशोक, नीरज समेत एक दर्जन मेडिकल स्टोर के संचालको ने पुलिस को तहरीर दी। दी गई तहरीर में बताया कि सूरज तिवारी पुत्र अनिल तिवारी निवासी नेवादा परस अपने साथ दो व्यक्ति अज्ञात व एक अज्ञात महिला के साथ बुधवार और गुरुवार को उन लोगों के मेडिकल स्टोर पर गए। जहां पर महिला को स्वास्थ विभाग का ड्रग इंस्पेक्टर बताकर मेडिकल स्टोर के अंदर घुस कर रखी दवाओं की जाँच करते हुए दवाओं की फोटो खींचने लगे ।कार्रवाई न करने की बात कहकर रुपयों की मांग की। कुछ मेडिकल स्टोर संचालक को कार्रवाई करने की बात कहकर धमकाते हुए अवैध वसूली की। वहीं संचालको ने संदिग्ध समझ कर उन लोगों से पूछताछ करने लगे ।

भीड़ जमा होते देख सभी लोग गाड़ी पर बैठकर भागने लगे। जिस पर पर मेडिकल संचालकों ने उनका पीछा भी किया ।बताया कि क्षेत्र में कई दिनों से यह लोग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बनकर मेडिकल स्टोरों व अस्पतालों में छापेमारी कर अवैध वसूली कर रहे थे ।इन लोगों ने गौरी चौराहा,नसीरपुर चौराहा, सुल्तानपुर, माधौगंज थाना क्षेत्र व उन्नाव जनपद के बार्डर के गांव चकहनुमान में संचालित कई मेडिकल स्टोरों पर जाँच पड़ताल की थी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोतवाल अनिल सैनी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज की गई है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

ड्रग इंस्पेक्टर स्वागतिका घोष ने बताया कि उनकी टीम के द्वारा कोई छापेमारी नहीं की जा रही है। छापमारी की सूचना उनको मिल रही थी। जिसकी सूचना उच्चाधिकारियो को दी गई थी।

शिव मंदिर परिसर में चला स्वच्छता अभियान

सोनभद्र(आरएनएस) । पीएम मोदी सेवा सप्ताह पखवाड़ा के अंतर्गत बुधवार को उरमौरा स्थित शिव मंदिर परिसर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। सदर ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत भाजपा जिला महामंत्री कृष्ण मुरारी गुप्ता के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाते हुए पीएम मोदी के संकल्प का दिया गया संदेश इस दौरान सदर ब्लाक प्रमुख अजीत रावत ने बताया कि अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा उसी क्रम में उरमोरा स्थित शिव मंदिर परिसर में साफ सफाई अभियान चलाया गया। प्रमुख ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए संकल्प को भाजपा कार्यकर्ता पूर्ण करने के लिए कार्य कर रहे हैं सेवा सप्ताह पखवाड़ा के अंतर्गत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें सभी कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष मंडल पर भारी सेक्टर अध्यक्ष व आम जनमानस के साथ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ कार्य किया जाएगा।

डीजे, डीएम, एसपी ने जिला जेल का किया संयुक्त निरीक्षण

बस्तीरू जिला जज कुलदीप सक्सेना, जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व पुलिस अधीक्षक गोपालकृष्ण चौधरी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ गुरुवार को जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरा के संचालन, सभी बैरकों में कैदियों की सघन तलाशी कराई। पाकशाला को देखा एवं भोजन की गुणवत्ता परखी। उन्होंने कैदियों से खानपान व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी ली। न्यायिक, प्रशानिक व पुलिस अधिकारी ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए कि मीनू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कैदियों को खाना व नाश्ता दिया जाए। सीसीटीवी कैमरों का संचालन निरंतर रहे। साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। कैदियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। बंदियों से वार्ता कर स्थिति का जायजा लिया। मौजूद सभी जेल कर्मियों को उनसे अपेक्षित समस्त कार्यवाहियों का निर्वहन सही तरीके से करने का निर्देश दिया। इस दौरान अधीक्षक जिला कारागार अंकेक्षिता श्रीवास्तव, जेलर राजीव कुमार मिश्र, पीआरओ एसपी पवन मिश्र, उप कारापाल रोशनजहां सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे ।निरीक्षण के दौरान जेल के बैरक, अस्पताल, मेस आदि का निरीक्षण कर कैदियों से वार्ता कर स्थिति का जायजा लिया गया एवं मौजूद सभी जेल कर्मियों को उनसे अपेक्षित समस्त कार्यवाहियों का निर्वहन सही तरीके से करने हेतु निर्देश दिया गया द्य निरीक्षण के दौरान पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक बस्ती व अन्य अधिकारीध् कर्मचारीगण मौजूद रहें।

योजना का लाभ लेकर आय बढ़ाए मछुआ समुदाय

राजापुर (चित्रकूट)। तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत रगौली में मछुआ समुदायों के बीच समिति की अध्यक्ष पार्वती देवी की अध्यक्षता में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मत्स्य विभाग अधिकारी दीपक मिश्रा मौजूद रहे।

मत्स्य विकास अधिकारी दीपक मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना के किनारे बसने वाले केवट, धीमर, घोघ, मल्लाह आदि जातियों के लिए मत्स्य आखेट पट्टे देने की योजना चलाई है। जिसमें मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड, पांच लाख रुपए का फ्री बीमा, साइकिल, मोटरसाइकिल, टाटा पिकअप 40 प्रतिशत के अनुदान पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना व मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना भी जनपद चित्रकूट में लागू की गई है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए मत्स्य विभाग से रेजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। समिति के सचिव राजकुमार निषाद व कमतू निषाद ने बताया कि जो लोग मोबाइल चलाते हैं वह फिशा फार्मर ऐप्प के माध्यम से पूरी जानकारी ले सकते हैं। बताया कि मत्स्य जीवी सहकारी समिति रगौली के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए मछुआ समुदाय के काफी लोग समिति के माध्यम से तालाबों की नीलामी लेकर मत्स्य पालन कर अपनी आय को दुगना करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मत्स्य जीवी सहकारी समिति रगौली की अध्यक्ष पार्वती ने कहा कि समाज को एकता के साथ व्यापार करना लाभप्रद है।

नगर थानाक्षेत्र के रानीपुर बेलाड़ी के रहने वाले थे शक्ति

बस्ती। अयोध्या में ढांचा गिराने के मामले में आरोपित रहे बजरंग दल के पूर्व प्रदेश संयोजक रहे रमेश प्रताप सिंह के बेटे की अपहरण व हत्या कर दी गई। शव को ठिकाने लगाने के लिए सरयू नदी के किनारे दो बोरे में भर कर फेंक दिया गया था। विभत्स तरीके से की गई हत्या की इस सनसनीखेज घटना में पुलिस मृतक शक्ति सिंह के भाई विक्रम प्रताप सिंह की तहरीर में की घटना में पूर्व विधायक राना किंकर सिंह के बेटे राना नागेश प्रताप सिंह समेत पांच लोगों पर अपहरण ,हत्या व शव को ठिकाने लगाने का मुकदमा नगर थाना पुलिस ने दर्ज किया है। बजरंग दल के नेता रहे रमेश प्रताप सिंह अयोध्या में ढांचा गिराने के मामले में पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवानी, उमा भारती, अशोक सिंघल के साथ मुकदमें में आरोपित थे।

अक्षिता को मिला कुलाधिपति स्वर्ण पदक

सुलतानपुर (आरएनएस)। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में मास्टर ऑफ परफार्मिंग आट्र्स की छात्रा अक्षिता शुक्ला को अपने विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में हुए '29वें दीक्षान्त समारोह में माननीय राज्यपाल के द्वारा कुलाधिपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। दीक्षान्त समारोह में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री रजनी तिवारी के साथ–साथ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रतिभा गोयल, अन्य शिक्षकगण एवं गणमान्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

बता दें कि इस विषय में कुल 4 सेमेस्टर थे जिनको मिलाकर अक्षिता ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है। अक्षिता ने इसका श्रेय अपने माता–पिता, विश्वविद्यालय के गुरुजन एवं परिवारजनों को दिया है। अक्षिता की शिक्षा स्टेला मॉरिस कान्वेन्ट स्कूल सुलतानपुर से हुई जिसकी पश्चात् उन्होंने डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से स्नातक और स्नातकोत्तर पूर्ण किया। ज्ञात हो कि हाल ही में जून 2024 में अक्षिता शुक्ला ने संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार में अपने प्रस्तुति दी थी जिसमें उन्हें केन्द्रीय संस्कृति मंत्री द्वारा 2,40,000ध– (दो लाख चालीस हजार रुपये) की धनराशि एवं प्रमाण–पत्र देकर सम्मानित भी किया गया था। पूर्व में देश–प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक मंच एवं महोत्सव पर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सम्मानित हुई हैं एवं विद्यालयों की सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका में रहीं हैं।

सूचना

सेवा में,
शाखा प्रबंधक
भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय
भरवारी कौशाम्बी 212201

सर्वाधिक सूचित किया जाता है, आवेदक रामपाल पुत्र बासदेव निवासी ग्राम व पो0 सैय्यद सरावॉ जिला कौशाम्बी का रहने वाला है जिसकी एल आई सी बीमा कि वर्ष 2007= मे दो पाल्सी न: 313326957=एवं 313326958 है जिसमे दोनो उपरोक्त पाल्सी मेँ त्रुटिवश नाम कंधईलाल यादव पुत्र बच्चू लाल यादव दर्ज हो गया है ।

जबकि आवेदक रामपाल पुत्र बासदेव का आधार कार्ड बैंक खाता आदि कागजात मे सही नाम व पता दर्ज है जो है रामपाल पुत्र बासदेव नि0 सैय्यद सरावॉ है। कधंई लाल यादव पुत्र बच्चूलाल यादव व रामपाल पुत्र बासदेव उक्त दोनो नाम व पता एक ही पढ़ा व समझा जाना न्याय हित मे आवश्यक है।

आवेदक/प्रार्थी
रामपाल पुत्र बासदेव
निवासी ग्राम व पोस्ट
सैय्यद सरावॉ/थाना
चरवा/तहसील चायल जिला
कौशाम्बी उ0प्र0
मो0/9918305469

अमृत कलश टाइम्स
हिन्दी दैनिक

अथक परिश्रम, दूरदर्षी सोच और कर्मठता से दुनिया में काबिज हुए।

रामपुर खास विधायिका व उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मण्डल दल नेता आराधना मिश्रा मोना ने रतन टाटा को सरल, सौम्य एवं परोपकारी स्वभाव के निर्विवाद उद्योगपति बताया। उन्होंने कहा कि वे अपने अथक परिश्रम, दूरदर्षी सोच और कर्मठता के कारण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख उद्योग पतियों में अपना नाम दर्ज कराया। वे जो लक्ष्य निर्धारित कर लेते थे उसको जब तक पूर्ण नहीं कर लेते थे तब तक कठिन मेहनत एवं लगन के साथ अपने कार्य में लगे रहते थे । उनके असमय चले जाने से देश की अपूर्णनीय क्षति हुई है जिसकी भरपाई कभी संभव नहीं हो सकती, और उद्योग जगत का एक चमकता हुआ ''सितारा'' सदा सर्वदा के लिये अस्त हो गया है । उन्होंने टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करें, तथा उनके परिजनों, शुभ चिन्तकों एवं सहयोगियों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

टाटा को भुलाया नहीं जा सकता।

उपनेता राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने उद्योग जगत के देदीप्यमान नक्षत्र तथा भारत का दुनिया में उद्योग केंद्र स्थापित करने में रतन टाटा का अविस्मरणीय योगदान है। मैं टाटा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुये श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वर्ष 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ तो देष बड़े उद्योग के क्षेत्र में शून्य था। हमारी निर्भरता इंगलैण्ड और अन्य देषों पर ज्यादा थी। पंडित नेहरू के सपनों को पूरा करने के लिये औद्योगिक क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने के लिये ''टाटा'' सबसे आगे आये। टाटा स्टील्स सहित तमाम संयंत्र लगाये। आज आधुनिक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में टाटा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

सादगी, आदर्श के प्रतीक रतन टाटाः राजेंद्र

प्रयागराज। प्रसिद्ध उद्योगपति पद्मिभूषण रतन टाटा के निधन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र ने कहा कि रतन टाटा ने राष्ट्र प्रथम को हनेशा सर्वोपरि रखा। सादगी परोपकार असीम सेवा भावना के आदर्श प्रतीक थे रतन टाटा। देश के आर्थिक सामाजिक विकास में उनके योगदान को चिरकाल तक नहीं भुलाया जा सकता। कुश श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी विवेक मिश्रा, मनोज कुशवाहा, आनंद दुबे,, राकेश भारती, प्रशांत शुक्ला, नवाब खान, राजेश गोंड, श्याम प्रकाश पांडेय, आस्तिक शुक्ला, संजय सिंह, चंद्रा अहलूवालिया, शिवा त्रिपाठी, बिलाल खान आदि ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की।

गुरूदत्त अखाड़ा में पट्टाभिषेक भण्डारा छब्बीस को

प्रयागराज। चौफटका स्थित अनंत माधव देवगिरी हनुमान मंदिर में 26

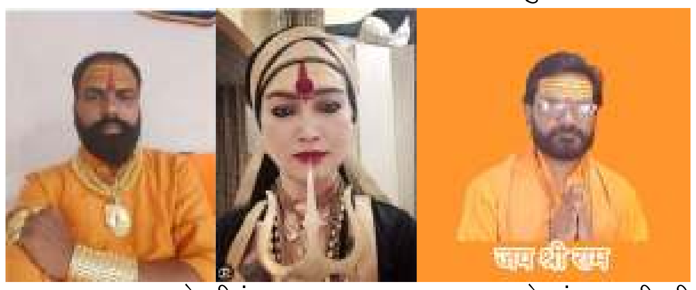

अक्टूबर गुरूवार को श्रीपंच दशनाम गुरुदत्त अखाड़ा के संरक्षक श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी चौतन्य गिरि महराज गुजरात, महामंडलेश्वर पद पर श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद गिरि महाराज , भवानी शंकर गिरि दिल्ली, आचार्य विनोद गिरि और स्वामी वीरेन्द्रानंद गिरि प्रयागराज का पट्टाभिषेक और विशाल भण्डारे का आयोजन किया गया है। यह भण्डारा पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू होकर देर शाम तक चलेगा। यह जानकारी स्वामी विरेन्द्रानंद महराज ने दी है। उन्होंने बताया कि इस दौरान महाकुंभ तीर्थराज की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होगी और छावनी प्रवेश (पेशवाई) चौफटका स्थित देवगिरी हनुमान मंदिर से महाकुम्भ मेला क्षेत्र के लिए होगी इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गयी है।

आरपीएफ ने दो शराब तस्कर को गिरफ्तार किया।

प्रयागराज। रेलवे सुरक्षा बल ने वित्तीय वर्ष 2024 –25 में शराब तस्करी के 24 मामले पंजीकृत कर 30 शराब तस्करों से 7,72,010৳– रुपये की शराब जप्त की। 18 अक्टूबर, 2024 को रेलवे सुरक्षा बलध्प्रयागराज के उप निरीक्षक टीपी सरोज एवं राजकीय रेलवे पुलिस के उप निरीक्षक पंकज कुमार सिंह ने स्टाफ ने टीम के साथ रेलवे के माध्यम से अवैध रूप से शराब की तस्करी व अन्य अपराधो को अंजाम देने वाले अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान में प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 4ध्5 से शराब तस्कर प्रभाकर सिंह पुत्र अनिल सिंह, उम्र 32 वर्ष, चमरूपुर नंदौत, फूलपुर प्रयागराज एवं जनार्दन सिंह पुत्र अनिल सिंह, उम्र 26 वर्ष चमरूपुर नंदौत, फूलपुर, प्रयागराज को भारी मात्रा में अवैध अग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। दोनों तस्करों से 180 एमएल वाले 121 ऑफिसर च्वाइस पाउच बरामद किए गए। जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि बरामद की गयी शराब की अनुमानित कीमत 14520৳– रुपये है । उक्त शराब तस्कर ट्रेनो के माध्यम से शराब की तस्करी कर बिहार प्रान्त ले जाकर ऊचे दामों में बेचने के अवैध कारोबार में संलग्न थे। उक्त शराब तस्करों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विधिक कार्यवाई की जा रही है।

उत्तर मध्य रेलवे

No. 10520242025 Dated: 17/10/2024

प्रथम शुद्धिपत्र

No. 10520242025 Dated: 11/10/2024 उपरोक्त निविदा सूचना में निम्नलिखित संशोधन किया गया है। निविदा सूचना सं.: 10520242025-228, कार्य का नामः DEN/E/PRYJ के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत PRYJ क्षेत्र में वनीकरण और हरित क्षेत्र का विकास। प्रकाशित अमानत राशिः ₹1,01,900.00, अमानत राशि, के रूप में पढ़ा जाए: ₹ 2,01,900.00. All other conditions will be remained same.

1794/24(DG)

व्यापारियों के मुट्ठियां भींचते ही उतरा रौब का रंग, पीडीए बोला– नहीं तोड़ेंगे कोई घर

प्रयागराज। प्रमुख मार्गों के किनारे घरों को निजी खर्चे पर एक रंग में रंगने से इन्कार पर ध्वस्तीकरण का नोटिस थमाने के खिलाफ मेयर–सांसद भी लोगों के साथ आ गए हैं। व्यापारी सीएम के नाम की चिट्ठी बना चुके हैं। इसे आज भेजेंगे। विरोध–प्रदर्शन देख पीडीए ने कहा, किसी का घर नहीं तोड़ेंगे। मंडलायुक्त ने भी पीडीए वीसी से बातचीत कर समाधान निकालने को कहा है। महाकुंभ की पांच हजार करोड़ से अधिक की सरकारी परियोजनाएं चल रहीं हैं, लेकिन प्रमुख मार्गों के रंगरोगन के लिए कोई बजट नहीं मिला है। पीडीए उपाध्यक्ष डॉ. अमित पाल शर्मा ने 28 सितंबर को दिए आदेश में चिह्नित 10 मार्गों पर अपने खर्चे से एक माह के भीतर रंगरोगन कराने को कहा है। नहीं कराने पर इसे प्राधिकरण कराएगा जरूर, लेकिन बाद में कार्रवाई भी करेगा। इसे लेकर कटरा, बैरहना, तेलियरगंज, झूंसी, नैनी, छिवकी, सुलेमसराय आदि इलाकों के लोगों ने रंगरोगन कराने में असमर्थना जताई है। हालांकि, सिविल लाइंस, एसपी मार्ग, एमजी मार्ग आदि में रंगरोगन शुरू हो गया है। पीडीए ने कटरा के दशकों पुराने भवनों के नक्शे का हवाला देकर ध्वस्तीकरण का नोटिस भेजने पर कटरा के व्यापारियों ने बृहस्पतिवार को भी जोरदार विरोध जताया। श्री कटरा व्यापार मंडल ने दोहराया है कि आम जनता और व्यापारी रंगाई–पोताई का खर्चा क्यों उठाएं। यह जिम्मेदारी पीडीए की है। उसे

ही इसका खर्च वहन करना चाहिए। दरअसल, पीडीए ने कटरा क्षेत्र में लक्ष्मी टॉकीज चौराहे से मनमोहन पार्क चौराहा एवं आनंद भवन से तहसील सदर जाने वाली सड़क पर बने मकान एवं प्रतिष्ठान एक रंग में रंगने को कहा गया है। इन्कार करने पर नोटिस देने के विरोध में कटरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद आनंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को व्यापारियों की बैठक हुई। तय हुआ कि व्यापारी इस मामले में शुक्रवार को सीएम योगी को पत्र भेजेंगे। आनंद अग्रवाल ने कहा कि पीडीए अफसर सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा कृत्य कर रहे हैं। यह निंदनीय है। व्यापारियों ने कहा कि अगर पीडीए अपने खर्च से रंग रोगन करवाता है तो व्यापारी और व्यापार मंडल पूरा सहयोग करेंगे। अगर इसी तरह से तानाशाही जारी रही तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। वहीं, व्यापार मंडल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल करने के लिए वकीलों की एक टीम गठित कर दी है। श्री कटरा व्यापार मंडल के संरक्षक अवधेश चंद्र गुप्ता की अगुवाई में बृहस्पतिवार को प्रतिनिधिमंडल फूलपुर सांसद प्रवीन पटेल से मिला। गोपाल बाबू जायसवाल ने उन्हें बताया कि रंगरोगन नहीं कराने पर सुलेम सराय, सिविल लाइंस और पूरे कटरा क्षेत्र में व्यापारियों को पीडीए नोटिस दे रहा है। इससे व्यापारियों में गहरा रोष है। व्यापारी अनुराग जायसवाल, प्रमेश जैन, गिरिश गुप्ता आदि ने कहा कि अधिकारी जानबूझकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। सांसद ने तुरंत ही कमिश्नर विजय विश्वास पंत से फोन पर बात की। कहा, मामले की गंभीरता समझें, फिर कोई कदम उठाएं। कमिश्नर ने दो दिन में भीतर समाधान निकालने का भरोसा दिया है। इसके बाद कमिश्नर ने पीडीए वीसी से बात की और लोगों को भरोसे में लेकर उचित समाधान निकालने के निर्देश दिए। वहीं, शहर के प्रथम नागरिक महापौर गणेश केसरवानी ने नोटिस की जानकारी से ही इन्कार किया। हालांकि, यह भी जोड़ा कि किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। न किसी का घर टूटेगा और न ही कोई अन्य कार्रवाई ही होगी। बढ़ते विरोध के बीच अब पीडीए के अधिकारी भी बैकफुट पर हैं। पीडीए के जोनल अधिकारी संजीव कुमार उपाध्याय का कहना है कि किसी का मकान नहीं गिराया जा रहा है। लोगों से रंग–रोगन कराने का अनुरोध किया है। इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी। कई लोगों ने रंग–रोगन शुरू भी कर दिया है। पूर्व पार्षद आनंद अग्रवाल का दावा है कि अफसरों की कार्यशैली बेनकाब होने के बाद पीडीए के जोनल अफसर संजीव उपाध्याय ने फोन किया था। उन्होंने कहा है कि व्यापारी सहयोग करें, पीडीए नोटिस वापस ले लेगा। आनंद के अनुसार उन्होंने जोनल अफसर से कहा है कि पीडीए अपने खर्चे से रंग रोगन कराए, जिसमें सभी व्यापारी सहयोग करेंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव विक्रांत पांडेय का कहना है कि पहले अपना मकान एक रंग में रंगवाने का आदेश देना और फिर दबाव बनाने के लिए मकान को अवैध निर्माण बताकर नोटिस देना पीडीए की तानाशाही को ही दर्शाता है। जब लोग सालों पहले अपने मकान बनवा रहे थे, तब पीडीए कहां था। इस मुद्दे पर हम व्यापारियों के साथ हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) द्वारा सिविल लाइंस क्षेत्र की दो प्रमुख सड़कों के भवनों एवं प्रतिष्ठानों को एक ही रंग में रंगे जाने का फरमान जारी किया गया है। यहां व्यापारी इस कार्य में सहयोग करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सिविल लाइंस क्षेत्र में तमाम भवन एवं शोरूम ऐसे हैं जिनकी बाहरी दीवारों पर पेंट नहीं बल्कि एसीपी लगी हुई है। इसे बदलवाने के लिए उन्हीं बड़ी रकम खर्च करनी होगी। बताया जा रहा है कि जिन शोरूम और प्रतिष्ठानों की बाहरी दीवारों पर एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी) लगा हुआ है, वह काफी निराश हैं। उनका कहना है कि इस पर रंग नहीं चढ़ सकता है। एक बार इसे लगवाने पर 20 से 25 वर्ष तक यह आसानी से चल जाता है। सिविल लाइंस व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील खरबंदा ने कहा कि यहां एमजी मार्ग एवं नवाब युसूफ रोड पर स्थित भवन, दुकान आदि को एक रंग में रंगा जाना है। व्यापारी सहयोग करने के लिए तैयार भी हैं लेकिन पीडीए ने 31 अक्तूबर तक यह कार्य पूरा करने का फरमान दिया है।

सुशील खरबंदा ने कहा कि दिवाली इसी माह है। इसी माह कारोबार ठीक चलता है। ऐसे में अगर व्यापारी रंगाई पुताई कराएंगे तो उसमें काफी समय लग जाएगा। उससे उनकी दुकानदारी भी प्रभावित होगी। वैसे भी इस समय रंगाई पुताई के लिए लेबर नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए पीडीए 31 अक्तूबर की तारीख को और आगे बढ़ाए। कहा कि रंग रोगन की वजह से जिन व्यापारियों को दिक्कतें हो रही हैं और जो अपना सुझाव देना चाहते हैं, उसे लेकर शनिवार 19 अक्तूबर को व्यापारियों की एक बैठक आयोजित की जा रही है।

हाईकोर्ट में पीएम मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। पीएम मोदी के खिलाफ नामांकन पत्र दाखिल करने वाले विजय नंदन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। जिसको उन्होंने अदालत में चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के सिवनी के रहने वाली विजय नंदन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से नामांकन पत्र भरा था, लेकिन बिना कोई कारण दर्शाए उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया था। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयोग सहित जिला निर्वाचन अधिकारी वाराणसी और पीएम नरेंद्र मोदी को प्रतिवादी बनाते हुए चुनाव याचिका दाखिल की है। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले संत विजय नंदन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कानूनी सलाह लेने की मोहलत दी थी। साथ ही कोर्ट ने याचिका दाखिल करने में हुई देरी पर भी हलफनामा मांगा था। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की अदालत कर रही है। याची संत ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। चुनाव याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने, याची के नामांकन को वैध करार देकर वाराणसी सीट पर फिर से चुनाव कराने, उचित मुआवजा दिए जाने और निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।

इविवि में खोली गई दशकों पुरानी तिजोरी, निकले 500 साल पुराने सोने के सिक्के और ताम्रपत्र

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के केंद्रीय पुस्तकालय में रखी दशकों पुरानी तिजोरी से तकरीबन पांच सौ साल पुराने सोने के सिक्के निकले हैं। साथ ही दो अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पाए गए, जिनमें पर्शियन भाषा में लिखा शाही फरमान और ताम्रपत्र पर अंकित पाली भाषा में विनय पिटक भी शामिल है। कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव की देखरेख में लगातार दूसरे दिन में तिजोरी के तीन लॉकरों को खोलने की कोशिश जा रही और आखिर इसमें सफलता मिली। तिजोरी के भीतर बहुमूल्य पुरातात्विक धराहरें मिलीं, जिसमें अलग–अलग काल और लिपियों में तकरीबन 500 सिक्के शामिल हैं। इनमें से कुछ सिक्के सोने के हैं। प्रारंभिक जांच में विशेषज्ञों ने इन सोने के सिक्कों को कश्मीर के एक आदिवासी समुदाय (किडाइट्स किंगडम) से जोड़ते हुए तकरीबन पांच सौ साल पुराना बताया है। इन सिक्कों पर ब्रह्मी लिपि अंकित है और इनका अनुवाद किसी केदार नाम के व्यक्ति ने किया है। सोने के ये सिक्के मध्यकालीन इतिहास के हैं और एक सिक्के का वजन 7.34 ग्राम और इसका व्यास 21 एमएम है और ये गोल आकार के सिक्के हैं। वहीं, अन्य धातुओं के सिक्कों के बारे में अभी कुछ खास पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक तौर पर इतनी ही जानकारी सामने आई है कि ये सिक्के अलग–अलग काल और लिपियों से संबंधित हैं। इनके अलावा तिजोरी से एक एक शाही फरमान निकला है, जो पर्शियन भाषा में लिखा गया है और ताम्रपत्र पर अंकित पाली भाषा में विनय पिटक पाया गया है। इविवि की पीआरओ प्रो. जया कपूर ने बताया कि कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्षा लॉकर खोला गय और उसमें रखी हुई पुरातात्विक धरोहरों की सूची तैयार की गई। समिति के समक्ष समस्त धरोहर सील लगाकर लॉकर में पुनः रख दी गईं हैं। इविवि की पीआरओ प्रो. जया कपूर ने बताया कि प्राप्त की गईं पुरातात्विक धरोहरों को विशेषज्ञों द्वारा विवरण सहित तैयार करके संग्रहालय की योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। इन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संग्रहालय में रखा जाएगा, जो शोधार्थियों के लिए शोध सामग्री के रूप में भी काम आएंगी। दशकों बाद पता चला कि इविवि के पास हैं अमूल्य धरोहरअगर कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव लॉकर का न खुलवातीं तो शायद यह भविष्य में भी लंबे समय तक राज ही बना रह जाता कि केंद्रीय पुस्तकालय में रखी तिजोरी में पुरातात्विक महत्व की अमूल्य धरोहरें बंद हैं। इस प्रयास के बाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए भी शोध के नए रास्ते खुले हैं। अब भी यह सवाल बना हुआ है कि इविवि के पास पुरातात्विक महत्व वाले ये सिक्के, शाही फरमान और विनय पिटक कब और कहां से आया? केंद्रीय पुस्तकालय में तिजोरी कब लाकर रखी गई? इस तिजोरी पर दशकों तक किसी का ध्यान क्यों नहीं किया? आखिर तिजोरी की चाभी कहां गई? ऐसे ही कई दूसरे सवाल भी इन पुरातात्विक महत्व की धरोहरों को लेकर उठ रहे हैं, जिनका जवाब भविष्य में इविवि प्रशासन द्वारा विशेषज्ञों से जांच कराए जाने पर मिल सकता है। सूत्रों का कहना है कि पूर्व कुलपति प्रो. खेत्रपाल के कार्यकाल में अंग्रेजी विभाग में शिक्षक रहे प्रो. मानस मुकुल दास के नेतृत्व में इस बाबत एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी देखरेख में यह तिजोरी केंद्रीय पुस्तकालय में रखी गई थी। इविवि केंद्रीय पुस्तकालय में रखी तिजोरी खोले जाने के मामले में छात्रों ने आरोप लगाया है कि यह कार्य नियम विरुद्ध किया गया। जिला प्रशासन के किसी प्रतिनिधि के समक्ष तिजोरी खुलवानी जानी चाहिए थी। इस मामले में समाजवादी छात्रसभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय यादव ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए कर्नलगंज थाने में तहरीर दी है। वहीं, छात्रों के विरोध को देखते हुए तिजोरी खोले जाने की प्रक्रिया के दौरान दोनों केंद्रीय पुस्तकालय के बाहर पुलिस फोर्स तैनात रही।

व्हाट्सएप, यूपीआई से गृहकर का भुगतान आसान।

प्रयागराज। मुख्य कर अधिकारी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि शुक्रवार को नगर निगम तथा बैंक ऑफ बड़ौदा की एक नई और अत्याधुनिक सेवा का उद्घाटन हुआ। नागरिकों को अपने गृह कर एवं जल कर इत्यादि की जानकारी और देय बिलों की याद दिलाने के लिए व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होंगी एवं नागरिकों को समय पर घर बैठे अपने करों का भुगतान करने में मदद करेगी और उन्हें लंबी कतारों और अन्य परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक मोबाइल आधारित एप्लिकेशन भी तैयार किया है, जो घर–घर जाकर संपत्ति कर, पानी कर और अन्य गैर–करों के संग्रहड़ मे मदद करेगा। यह सेवा नागरिकों को उनके दरवाजे पर ही सुविधाजनक रूप से कर जमा करने की सुविधा प्रदान करेगी। इसके साथ ही, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक और नवोन्मेषी कदम उठाया है एआई कैमरा टेक्नोलॉजी का उपयोग। यह कैमरा अवैध और अनधिकृत होर्डिंग्स की पहचान करेगा, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा होने की स्थिति का निरीक्षण करेगा और टूटी हुई स्ट्रीट लाइट्स की जानकारी देगा। यह तकनीक नगर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसका इस्तेमाल आने वाले महाकुंभ मे भी किया जाएगा

सिपाही पर दर्ज गैर इरादतन हत्या मामले की जांच छह सप्ताह में पूरी करें, कोर्ट ने दिया आदेश

प्रयागराज। हाईकोर्ट ने गाजीपुर के गहमर थाने के सिपाही पर दर्ज गैर इरादतन हत्या के मामले की जांच छह सप्ताह में पूरी करने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने राजकिशोर सिंह की याचिका पर दिया। शिकायतकर्ता राजकिशोर सिंह निवासी ग्राम गहमर पट्टी भैरो राय, गहमर ने सिपाही व दो अन्य पर बेटे विकास कुमार सिंह की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। सिपाही पर नौकरी लगवाने के नाम पर बेटे से पांच लाख रुपये लेने का आरोप भी लगाया था। राजकिशोर ने पुलिस की ओर मामले की विवेचना शीघ्र कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची के वकील राकेश प्रताप सिंह ने दलील देते हुए मामले की शीघ्र, निष्पक्ष व उचित जांच करने की कोर्ट से प्रार्थना की।

भगवान शिव की मूर्ति तोड़ने के आरोपी को नहीं मिली जमानत, नफरत पैदा करने वालों के साथ नरमी नहीं

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सावन में भगवान शिव की मूर्ति तोड़ने व पुजारी पर चाकू से हमला करने के आरोपी शाहरुख की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कहा कि ऐसे अपराध, जिनसे लोगों या समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा मिलता है, उन्हें सख्ती से दबाना होगा। समुदाय और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों पर नरम रुख अपनाकर इन अपराधों।

महाप्रबंधक ने मेमू कार शेड और इलेक्ट्रिक लोको शेड का भी निरीक्षण।

प्रयागराज। शुक्रवार को कानपुर परिक्षेत्र के दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे श्री उपेंद्र चंद्र जोशी ने उप मंडलीय चिकित्सालय कानपुर में नवनिर्मित बिल्डिंग का शुभारंभ किया। इस नवनिर्मित बिल्डिंग में रजिस्ट्रेशन काउंटर, अत्याधुनिक पैथोलॉजी और दवाओं के वितरण हेतु काउंटर्स की व्यवस्था है। इस अवसर पर मंडल प्रयागराज मंडल हिमांशु बडोनी, उप मुख्य यातायात प्रबंधक, कानपुर आशुतोष सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कानपुर रविंद्र प्रसाद सहित मेडिकल एवं अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। महाप्रबंधक ने मेमू कार शेड और इलेक्ट्रिक लोको शेड का भी निरीक्षण किया और वहां की कार्यप्रणाली के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली।

सम्पादक
सिद्धनाथ द्विवेदी
प्रबन्धक निदेशक
दीपक जयसवाल
सम्पादकीय कार्यालय
11ई/2, ताशकंद मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के आधीन होगा।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक सिद्धनाथ द्विवेदी द्वारा काम्पीटेंट बिजनेस सर्विसेज विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित एवं 399 कृष्णानगर कीडगंज से प्रकाशित।
सम्पादक–सिद्धनाथ द्विवेदी, आरएनआई नं. UPHIN/2007/22706 रजि.नं. AD-32/2008-09 ईमेलः amritkt.alld@gmail.com फोन नं. : 9453273951, 8799627062